नीति आयोग के कार्यों के बारे में जानें व PDF में नोट्स डाउनलोड करें!

भारत के परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्थान, जिसे नीति आयोग के नाम से भी जाना जाता है। जिसे भारत सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में सेवा के लिए बनाया गया है। संस्थान केंद्र सरकार की नीति बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करता है और भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति पर नज़र रखता है। इस लेख में हम नीति आयोग के संविधान, इसकी शासी परिषद संरचना, नीति आयोग के कार्यों और नीति आयोग द्वारा शुरू की गयी नयी पहलों पर चर्चा करेंगे। नीति आयोग के बारे में विस्तार से जानकारी रखना बेहद आवश्यक है क्योंकि विभिन्न सरकारी व बैंकिग परिक्षाओं में इस पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

आप इस लेख के अंत में शब्दावली को इस लेख में उपयोग किए गए कुछ इटैलिक एस्ट्रिक चिह्नित शब्दों के अर्थ को समझने के लिए भी देख सकते हैं:

testbook.com

नीति आयोग

नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय कैबिनेट के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया था। भारत सरकार ने अपने सुधार एजेंडे के अनुरूप 1950 में स्थापित योजना आयोग को बदलने के लिए नीति आयोग का गठन किया। यह सेवा करने के लिए किया गया था बेहतर तरीके से भारत के लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को बेहतर तरीके से सेवा देने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। अतीत से एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में, नीति आयोग राष्ट्रीय सरकार में राज्यों को राष्ट्रीय हित में एक साथ कार्य करने के लिए भारत के प्रमुख मंच के रूप में कार्य करता है, और इस प्रकार * सहकारी संघवाद * को बढ़ावा देता है।

नीति आयोग की रचना के मूल में दो केंद्र हैं - टीम इंडिया हब और ज्ञान व अभिनव हब। टीम इंडिया हब केंद्र सरकार के साथ राज्यों की भागीदारी का नेतृत्व करता है, जबकि ज्ञान व इनोवेशन हब नीति आयोग की थिंक टैंक क्षमताओं का निर्माण करता है। नीचे दिए गए लेख में नीति आयोग के संविधान, गवर्निंग काउंसिल की रचना, नीति आयोग के कार्यों और नई पहल की शुरूआत के बारे में जानें।

नीति अयोग का संविधान

Chairperson

Shri Narendra Modi, Hon'ble Prime Minister

Vice Chairperson

Dr. Rajiv Kumar

Full-Time Members

Dr. Bibek Debroy

Shri V.K. Saraswat

Prof. Ramesh Chand

Dr. V. K. Paul

Ex-officio Members

Shri Rajnath Singh, Minister of Home Affairs

Shri Arun Jaitley, Minister of Finance and Minister of Corporate Affairs

Shri Piyush Goyal, Minister of Railways

Shri Radha Mohan Singh, Minister of Agriculture and Farmers Welfare

Special Invitees

Shri Nitin Jairam Gadkari, Minister of Road Transport and Highways and Minister of Shipping

Shri Thaawar Chand Gehlot, Minister of Social Justice and Empowerment

Smt. Smriti Zubin Irani, Minister of Textiles.

Chief Executive Officer

Shri Amitabh Kant

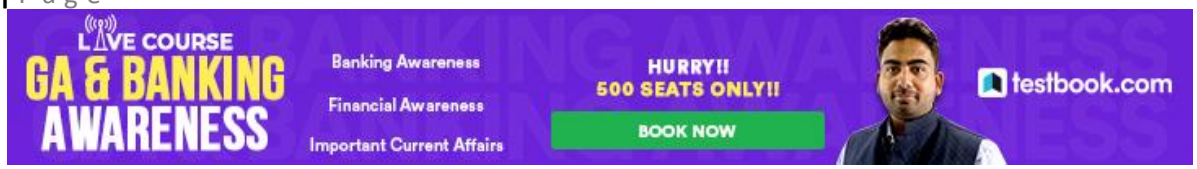

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की संरचना

नीति आयोग की शासी परिषद में भारत के 29 राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ मंत्री शामिल हैं। इसके पूर्णकालिक कर्मचारी - एक डिप्टी चेयरमैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और विशेषज्ञ - सीधे प्रधानमंत्री को उत्तरदायी, जो राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष पद का पद धारण करते हैं।

नीति आयोग के कार्य

1. नीति आयोग (भारत को बदलने के लिए राष्ट्रीय संस्थान) के कार्यों का विस्तार से नीचे उल्लेख किया गया है:
i. राष्ट्रीय विकास प्राथमिकता क्षेत्रों और रणनीतियों पर राज्य सरकारों के साथ काम करने के लिए

- संघीयवाद विकसित करें जहां राष्ट्रीय और राज्य सरकारें उचित समन्वय और सद्भाव के साथ काम करती हैं।
- ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं और पहलों को लागू करें।
- सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आर्थिक रणनीति और नीति कार्य करती हैं।
- प्रमुख हितधारकों और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समान विचारधारा वाले विचार टैंकों के साथ-साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच साझेदारी को सलाह दें और प्रोत्साहित करें।
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों और अन्य भागीदारों की सहायता से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता समर्थन प्रणाली बनाएं।
- एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाए रखें, सुशासन पर एक शोध केंद्र और स्थायी * और न्यायसंगत * विकास में सर्वोत्तम प्रथाएं बनें।
- कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन पर सक्रिय रूप से निगरानी और मूल्यांकन करें और इसके लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन * और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करें।

ii. राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी)

iii. नीति आयोग के कार्यों में से एक यह है कि यह योजना आयोग के हित में उत्तराधिकारी है।

नीति आयोग - नयी पहल

अपनी स्थापना के बाद से * संस्थान ने अर्थव्यवस्था के विकास और देश के हर नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई पहल की है। 31 मार्च 2017 से पंचवर्षीय योजनाओं को बदलने के बाद, नीति आयोग 15 साल की अवधि के अंत में निर्धारित सामाजिक लक्ष्यों के अनुरूप आने वाले 15 वर्षों के लिए एक दृष्टि दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया में है। नीति आयोग द्वारा की गई पहल की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- **मॉडल लैंड लीजिंग लॉ** - जमीन और उप-भूमि के बाहर और बाहर पट्टे की बढ़ती घटनाओं पर ध्यान देना * कम संख्या में किसानों के साथ भूमि का उपयोग, नीति आयोग ने किरायेदार के अधिकारों को पहचानने के लिए मॉडल कृषि भूमि लीजिंग अधिनियम, 2016 तैयार किया है और भूमि मालिकों के हितों की भी रक्षा की है।
- **कृषि उत्पादन विपणन समिति अधिनियम के सुधार** - नीति आयोग ने 21 अक्टूबर 2016 को तीन महत्वपूर्ण सुधारों पर राज्यों से परामर्श किया -
    - कृषि विपणन सुधार
    - निजी भूमि पर उगाए जाने वाले पेड़ के उत्पादन के लिए फेलिंग और ट्रांजिट
    - कानूनकृषि भूमि पट्टे पर
- **मेडिकल एजुकेशन को सुधारना** - उपाध्यक्ष द्वारा की गई एक समिति, नीति आयोग ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्क्रैपिंग * की सिफारिश की और मेडिकल शिक्षा को विनियमित करने के लिए एक नया निकाय सुझाया। प्रस्तावित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के लिए मसौदा कानून सरकार को और आवश्यक कार्रवाई के लिए जमा कर दिया गया है।
- **डिजिटल भुगतान आंदोलन** -
    - नीति आयोग ने 30 नवंबर 2016 को आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ पारदर्शिता, वित्तीय समावेश और राष्ट्रव्यापी स्वस्थ वित्तीय पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के लिए संयोजक के रूप में डिजिटल भुगतान पर मुख्य मंत्रियों की एक समिति गठित की।
    - डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए * राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के लिए, रुपये की केंद्रीय सहायता। डिजिटल मंच पर 5 करोड़ जन धन खातों को लाने के लिए जिलों को सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के उपक्रम के लिए 50 करोड़ रूपए दिए जाएंगे।
    - भीम ऐप के माध्यम से डिजिटल भुगतान के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 14.4.2017 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा कैशबैक और रेफ़रल बोनस योजनाएं शुरू की गईं।
    - नीती अयोग ने समाज के सभी वर्गों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए दो प्रोत्साहन योजनाएं भी शुरू की - भाग्यशाली ग्राहक योजना और डिजी धन व्यापर योजना- जिसके तहत 16 लाख उपभोक्ताओं और व्यापारियों ने 256 करोड़ रुपये जीते।

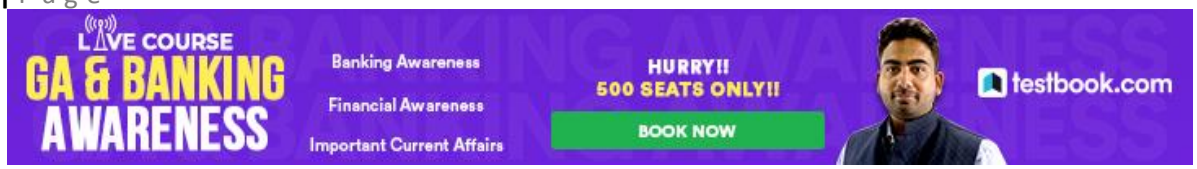

testbook PASS ATTEMPT ALL TESTS ACROSS ALL EXAMS ₹599 FOR 1 YEAR BUY NOW testbook

- **अटल इनोवेशन मिशन** - सरकार ने नीति आयोग में अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) की स्थापना की है ताकि संस्थानों और कार्यक्रमों को बनाकर देश के नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत किया जा सके, जो सामान्य रूप से स्कूलों, कॉलेजों और उद्यमियों में नवाचार को बढ़ावा देगा।
- **भारत में गरीबी उन्मूलन पर कार्य बल** - 16 मार्च, 2015 को नीति अयोग के उपाध्यक्ष डॉ अरविंद पानगारीय की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया और 11 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री को सौंप दिया गया, 2016. टास्क फोर्स की रिपोर्ट मुख्य रूप से गरीबी से निपटने के लिए गरीबी और रणनीतियों के मुद्दों पर केंद्रित है।
- **कृषि विकास पर कार्य बल** - यह 16 मार्च, 2015 को एनआईटीआई अयोध के उपाध्यक्ष डॉ अरविंद पानगारीय की अध्यक्षता में गठित किया गया था। टास्क फोर्स ने अपने कार्यों के आधार पर "कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों के लिए योग्य खेती करने के उपाय" नामक एक प्रासंगिक पत्र तैयार किया। यह भारतीय कृषि के 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित है जो हैं:
  (i) उत्पादकता बढ़ाना,
  (ii) किसानों को लाभकारी मूल्य,
  (iii) भूमि लीजिंग, भूमि अभिलेख और भूमि शीर्षक;
  (iv) पूर्वी हरित क्रांति-पूर्वी राज्यों पर ध्यान केंद्रित; तथा
  (v) किसानों की परेशानी का जवाब देना।
- **भारत के व्याख्यान श्रृंखला को बदलना** - सरकार के प्रमुख विचार-टैंक के रूप में, नीति आओग ने ज्ञान निर्माण और हस्तांतरण को राज्यों में वास्तविक परिवर्तन के रूप में देखता है। राज्यों और केंद्रों के लिए ज्ञान प्रणाली बनाने के लिए, नीति आयोग ने 26 अगस्त 2016 को प्रधान मंत्री के पूर्ण समर्थन के साथ 'नीति व्याख्यान: ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया' श्रृंखला शुरू की। व्याख्यान श्रृंखला का उद्देश्य सरकार की शीर्ष नीति बनाने वाली टीम को संबोधित करना है। भारत के कैबिनेट के सदस्यों और नौकरशाही की कई शीर्ष लेयर सहित।
- **हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद** - हिमालयी क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग ने हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद का गठन किया है। यह परिषद पहचाने गए कार्य बिंदुओं की समीक्षा और कार्यान्वयन करेगी।
- **शहरी आधारभूत संरचना पर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन** - सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) और नगर निगम नवाचारों के नए दृष्टिकोण नई दिल्ली में आयोजित किए गए। यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के लिए एशिया और प्रशांत (यूएनईएससीएपी) और एशियाई विकास बैंक के साथ साझेदारी में नीति आयोग द्वारा आयोजित किया गया था।

CURRENT AFFAIRS FASTEST WAY TO PREPARE CURRENT AFFAIRS GET IT ON Google Play

- **आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता** - नीति आयोग ने आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस (एआई) प्रौद्योगिकियों को तैनात करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ एक समझौता किया है। यह कृषि और स्वास्थ्य देखभाल में चुनौतियों का समाधान करेगा और दूसरों के बीच स्थानीय भाषा कंप्यूटिंग को अपनाने को बढ़ावा देगा। यह साझेदारी नीति आयोग को पायलटों को आगे बढ़ने में मदद करेगी। यह सार्वजनिक सामानों के प्रीपेन्डरेंस * द्वारा विशेषता क्षेत्रों में एआई कार्यान्वयन को मापने के तरीके को समझने में भी मदद करेगा।

ग्लोसरी :

- **निर्णायक** -किसी और चीज के विकास या सफलता के संबंध में बेहद महत्वपूर्ण।
- ***बढ़ावा*** - *विकास के लिए प्रोत्साहित करना।*
- **सहकारी संघवाद** - संघीयवाद की एक अवधारणा जिसमें राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारें आम समस्याओं को हल करने के लिए सहकारी और सामूहिक रूप से बातचीत करती हैं
- **स्थायी** - सक्षम एक निश्चित दर या स्तर पर बनाए रखा जाएगा।
- **न्यायसंगत** - निष्पक्ष।
- **उन्नयन** - किसी चीज की गुणवत्ता या उपयोगिता में सुधार करने की प्रक्रिया, या व्यक्ति को एक और महत्वपूर्ण नौकरी देने की प्रक्रिया।
- **उत्तराधिकारी** - एक व्यक्ति या चीज जो दूसरे को सफल बनाती है।
- **शुरूआत** - संस्था या गतिविधि की स्थापना या प्रारंभिक बिंदु।
- **उपोक्त** - उच्चतम मानक या गुणवत्ता से कम।
- **स्क्रैपिंग** - सेवा से हटा दें।
- **प्रोत्साहन** - कुछ करने के लिए प्रेरित (प्रोत्साहित) या प्रोत्साहित करें।
- **प्रेरणा** - एक बात यह है कि संकेत देता है या किसी को प्रोत्साहित करती है।
- **प्रीपेन्डरेंस** - संख्या, मात्रा या महत्व में अधिक होने की गुणवत्ता या तथ्य।

आशा है कि आपको नीति आयोग के संविधान, नीति आयोग के कार्यों आदि के बारे में आवश्यक जानकारी मिली है। क्या यह लेख आपके लिए उपयोगी था? नीचे दी गई टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें। सामान्य ज्ञान अनुभाग में बेहतर स्कोरिंग के लिए अपने ज्ञान को अपग्रेड करने के लिए ऐसे अधिक लेख देखें।

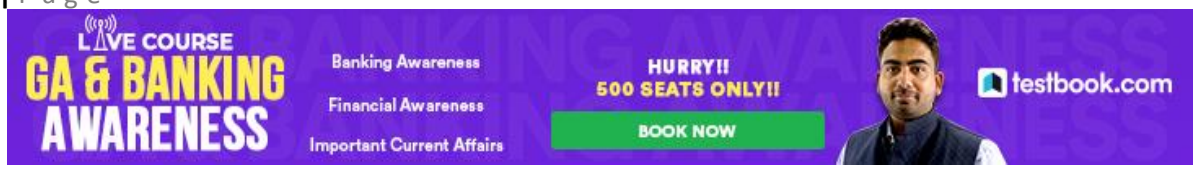

भारतीय चुनाव प्रक्रिया	भारतीय निर्वाचन आयोग
मुद्रा बाजार व कमोटिडी बाजार के बारे में जाने	पुस्तक और लेखक करंट अफेयर्स 2018

जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभ्यास सफलता की कुंजी है। अपना अभ्यास शुरू करके अपनी तैयारी को बढ़ावा दें।

मुफ्त में प्रश्नों को हल करें

टेस्टबुक पर अपने संदेहों को दूर करने के लिए आप अपने साथी उम्मीदवारों और हमारे विशेषज्ञों से भी बातचीत कर सकते हैं:

टेस्टबुक डिसकस से जुड़ें!

testbook.com